पटना उच्च न्यायालय की न्यायाधिकारिता में

2022 की लेटर्स पेटेंट अपील संख्या- 399

में

2022 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला संख्या- 9632

=====
आशुतोष कुमार, चंद्रेश्वर शर्मा के पुत्र, बिशुनपुर गिद्धा, थाना-मनियारी, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार के निवासी।

... ..अपीलार्थी।

बनाम

1. बिहार राज्य
2. प्रधान सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार, पटना।
3. संयुक्त सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. बिहार लोक सेवा आयोग पटना अपने सचिव के माध्यम से।

... ..उत्तरदातागण।

=====
उपस्थिति :

अपीलार्थी के लिए : श्री सत्यबीर भारती, वरिष्ठ अधिवक्ता।

श्री प्रिंस कुमार मिश्रा, अधिवक्ता।

राज्य के लिए : श्री प्रतीक कुमार, जी. ए.-5 के एसी

बीपीएससी के लिए : श्री निशांत कुमार, अधिवक्ता।

=====
आरक्षण – अनुसूचित जनजाति की स्थिति – सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का प्रभाव – बिहार सरकार की अधिसूचना दिनांक 23.08.2016 द्वारा 'लोहार जाति' को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया था, जिसे सर्वोच्च न्यायालय ने 21.02.2022 को असंवैधानिक घोषित कर दिया। (पैरा-4)

यदि किसी आरक्षण का कानूनी आधार नियुक्ति से पहले ही समाप्त हो गया हो, तो उम्मीदवार अनुसूचित जनजाति के लाभों का दावा नहीं कर सकता। (पैरा-10)

भर्ती प्रक्रिया – आवेदन जमा करने की तिथि के बाद नीति परिवर्तन का प्रभाव – आवेदन की अंतिम तिथि केवल शैक्षिक योग्यता और प्रक्रियात्मक अनुपालन के लिए प्रासंगिक है, न कि जाति की स्थिति के लिए(पैरा-11)

– यदि सर्वोच्च न्यायालय ने किसी जाति की एसटी स्थिति को अमान्य कर दिया है, तो उम्मीदवार का एसटी श्रेणी के तहत दावा मान्य नहीं रहेगा, भले ही उसने निर्णय से पहले आवेदन किया हो। (पैरा-12)

न्यायिक पुनरावलोकन – आरक्षण नीति के मामलों में सीमित हस्तक्षेप – उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को निरस्त नहीं कर सकता, जिसमें किसी जाति की एसटी स्थिति को असंवैधानिक घोषित किया गया हो।(पैरा-13)

– केवल चयन सूची में शामिल होने से किसी उम्मीदवार को नियुक्ति का अटल अधिकार नहीं मिलता। (पैरा-14)

निर्णय

– दिनांक 13.07.2022 का विवादित आदेश बरकरार रखा गया, यह पुष्टि करते हुए कि अपीलकर्ता सर्वोच्च न्यायालय के 21.02.2022 के निर्णय के बाद एसटी लाभ का दावा नहीं कर सकता। (पैरा-14)

– अपील खारिज कर दी गई, और अपीलकर्ता को सरकारी अधिसूचना दिनांक 19.04.2022 के अनुसार आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EBC) श्रेणी में लाभ लेने का निर्देश दिया गया। (पैरा-15)

संदर्भित मामले- सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य, WP(C) No. 1052 of 2021

– तेज प्रकाश पाठक बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय, (2024) LiveLaw (SC) 864 – बिहार राज्य बनाम मिथिलेश कुमार, (2010) 13 SCC 467 – भारतीय संविधान के अनुच्छेद 341 एवं 342 मामले की टिप्पणी: यह मामला पुष्टि करता है कि एक बार जब सर्वोच्च न्यायालय किसी जाति की एसटी स्थिति को अमान्य घोषित कर देता है, तो आरक्षण के लाभ को पूर्वव्यापी प्रभाव से दावा नहीं किया जा सकता। यह भी स्थापित करता है कि केवल चयन सूची में शामिल होने से नियुक्ति का अटल अधिकार उत्पन्न नहीं होता। यह निर्णय आरक्षण नीतियों में सीमित न्यायिक हस्तक्षेप को रेखांकित करता है, ताकि केवल संवैधानिक रूप से मान्य जातियों को एसटी लाभ प्राप्त हो।

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

=====

गणपूर्ति/कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री

और

माननीय न्यायमूर्ति श्री सुनील दत्ता मिश्रा

मौखिक निर्णय

(द्वारा/निर्णय: माननीय न्यायमूर्ति श्री पी. बी. भजंत्री)

तिथि – 03-03-2025

इस तत्काल एल. पी. ए. में, अपीलार्थी ने 2022 के C.W.J.C. संख्या- 9632 में पारित दिनांक 13.07.2022 के विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी है।

2. अपीलार्थी बिहार के सरकारी इंजीनियरिंग महाविद्यालय में सहायक प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के पद पर भर्ती के लिए एक उम्मीदवार था, जो 2020 के विज्ञापन No.52 दिनांक 09.09.2020 के अनुसार था। उन्होंने अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत अपनी उम्मीदवारी का दावा किया था। उन्होंने आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि से पहले यानी 12.10.2022 को इस पद के लिए आवेदन किया था। उन्होंने चयन प्रक्रिया में भाग लिया था। वह लिखित परीक्षा में सफल रहे और उन्हें 02.04.2022 को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया गया। दिनांक 06.05.2022 को भी उनके नाम की सिफारिश की गई थी।

3. राज्य सरकार ने 2016 की राजपत्र अधिसूचना संख्या 689 दिनांक 23.08.2016 जारी की थी, जिसमें लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया था। अपीलकर्ता ने 23.08.2016 की उक्त राजपत्र अधिसूचना के तहत 10.09.2016 को अनुसूचित जनजाति जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया था, जिसमें लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल किया गया था।

4. दिनांक 23.08.2016 को 'लोहार जाति को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करना' माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका (सिविल) संख्या 1052/2021 (सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य) में मुकदमे का विषय था, जिसमें 21.02.2022 को इसे खारिज कर दिया गया। इस पृष्ठभूमि में, विचारणीय प्रश्न यह है कि क्या अपीलकर्ता एसटी श्रेणी के तहत सहायक प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के पद पर चयन और नियुक्ति के उद्देश्य से अनुसूचित जनजाति

लाभ का दावा करने का हकदार है, इस तथ्य के मद्देनजर कि उसका नाम 06.05.2022 को उपर्युक्त श्रेणी के तहत नियुक्ति के लिए अनुशंसित किया गया है या नहीं?

5. तिथियों और घटनाओं को ध्यान में रखते हुए, यह स्पष्ट है कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी (लोहार जाति) के तहत सहायक प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के पद पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने वाले अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश की तारीख पर प्राधिकरण द्वारा यह ध्यान नहीं दिया गया था कि जहां तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 'अनुसूचित जनजाति सूची में लोहार जाति' को 21.02.2022 को समावेश/शामिल करने की बात है, सरकारी राजपत्र अधिसूचना को 23.08.2016 को रद्द कर दिया गया था। उस प्रभाव के लिए, अधिकारियों ने अपीलार्थी के नाम की सिफारिश करते हुए **सुनील कुमार राय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य** (ऊपर उद्धृत) के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर ध्यान नहीं दिया है। इसके बाद, अपीलार्थी के नाम पर विचार नहीं किया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उन्होंने 2022 का C.W.J.C. संख्या No.9632 दाखिल करने के लिए इस न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था और इसे खारिज कर दिया गया था। इसलिए एल. पी. ए. दाखिल किया गया है।

6. अपीलार्थी के विद्वान वकील ने प्रस्तुत किया कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक उम्मीदवार की जो भी स्थिति हो, उसे ध्यान में रखा जाना आवश्यक है। वर्तमान मामले में, आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 12.10.2020 है, उस तारीख तक, राजपत्र अधिसूचना दिनांक 23.08.2016 जहाँ तक 'अनुसूचित जनजातियों की सूची में लोहार जाति' को शामिल करने की बात है, कानून की नज़र में बहुत कुछ मौजूद था। इसलिए, 2020 के विज्ञापन No.52 दिनांक 09.09.2020 को प्रभावी बनाने और चयन और नियुक्ति की प्रक्रिया को पूरा करने के लिए, अपीलार्थी की उम्मीदवारी पर अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत विचार किया जाना आवश्यक है। अनुसूचित जनजाति श्रेणी या कोटे के तहत चयन सूची से अपीलार्थी का नाम बाहर करना और नियुक्ति का आदेश जारी नहीं करना गलत है। उपरोक्त दलीलों के समर्थन में, उन्होंने **आर. उन्नीकृष्णन और अन्य बनाम वी. के. महानुदेवन और अन्य, (2014) 4 उच्चतम न्यायालय के मामलों 434 (पैराग्राफ-12, 34 से 36 और 40 से 42) में रिपोर्ट किए गए और बिहार राज्य और अन्य बनाम मिथिलेश कुमार, (2010) 13 सर्वोच्च न्यायालय के मामलों 467 (पैराग्राफ-18 से 20) में रिपोर्ट किए गए** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दो फैसलों का हवाला दिया है।

7. इसके विपरीत, उत्तरदाताओं के विद्वान वकील ने उपरोक्त दलीलों का विरोध किया और प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी को चयन और नियुक्ति के लिए दावा करने का कोई अक्षम्य अधिकार नहीं है। उनका नाम केवल एसटी श्रेणी के तहत सहायक प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए उनके नाम पर विचार करने के उद्देश्य से चुना गया है। उन्हें इस पद/पोस्ट पर दावा

करने का कोई निहित अधिकार नहीं है। इस संबंध में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बार-बार कहा कि केवल चयन सूची में उम्मीदवार का नाम शामिल करने से, वह पद के लिए दावा करने का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इस तथ्य के आलोक में कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत सहायक प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के पद पर चयन और नियुक्ति के लिए अपीलकर्ता के नाम की सिफारिश की तारीख 06.05.2022 को, सरकारी राजपत्र अधिसूचना दिनांक 23.08.2016 के माध्यम से 'अनुसूचित जनजाति सूची में लोहार जाति' को शामिल करने से संबंधित आधार सामग्री को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सुनील कुमार राय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (उपरोक्त संदर्भित) के मामले में 21.02.2022 को रद्द कर दिया गया है। इसलिए, अधिकारियों ने 06.05.2022 को अपीलार्थी के नाम की सिफारिश की तारीख तक माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर ध्यान नहीं दिया है। इस बीच, जी. ए. डी. (GAD) ने मेमो No.6026 दिनांक 19.04.2022 के माध्यम से अधिसूचना जारी की जिसके द्वारा उसने अनुसूचित जाति प्रमाण पत्र और 'लोहार' जाति के अन्य लाभों को रद्द कर दिया और निर्णय लिया कि 'लोहार' जाति के उम्मीदवार ई. बी. सी. (EBC) श्रेणी के तहत अपने आरक्षण को बहाल करेंगे। चयन प्राधिकरण द्वारा चयन सूची में अपीलार्थी का नाम शामिल करते समय इस महत्वपूर्ण दस्तावेज़ की भी अनदेखी की गई थी। अपीलार्थी की ओर से उद्धृत निर्णय विषय के तथ्यात्मक पहलुओं को ध्यान में रखते हुए गलत हैं। आर. उन्नीकृष्णन और अन्य बनाम वी. के. महानुदेवन और अन्य (ऊपर उद्धृत) के मामले में, वे थे वर्ष 1987 में नियुक्त किया गया था जबकि वर्ष 1999 में कारणदर्शक/बताओ नोटिस जारी किया गया था। बिहार राज्य और अन्य बनाम मिथलेश कुमार (ऊपर उद्धृत), के मामले में यह प्रस्तुत किया गया है कि मामले के तथ्यात्मक पहलू अलग हैं।

8. संबंधित पक्षों के विद्वान वकील को सुना।

9. वर्तमान सूची में शामिल मुख्य मुद्दा यह है कि क्या अनुसूचित जनजाति कोटा/श्रेणी के विरुद्ध सहायक प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के पद के लिए अपीलार्थी के नाम पर विचार किया जाना आवश्यक है या नहीं?

10. निर्विवाद तथ्य यह है कि 23.08.2016 को, राज्य सरकार ने 'अनुसूचित जनजाति सूची में लोहार जाति' को शामिल करने के लिए एक राजपत्र अधिसूचना जारी की। उपरोक्त राजपत्र अधिसूचना के अनुसार, अपीलार्थी ने 'लोहार जाति' होने के नाते आवेदन प्रस्तुत किया और 10.09.2016 को अनुसूचित जनजाति श्रेणी का जाति प्रमाण पत्र प्राप्त किया। चयन अधिकारियों ने सहायक प्रोफेसर, कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के पद को 09.09.2020 पर अधिसूचित किया। एक उम्मीदवार होने के नाते अपीलार्थी ने अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत अपना दावा प्रस्तुत किया। वह लिखित परीक्षा में

सफल रहे हैं और उन्हें 02.04.2022 को साक्षात्कार के लिए बुलाया गया था। 21.02.2022 को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 की राज्य सरकार की राजपत्र अधिसूचना No.689 दिनांक 23.08.2016 को **सुनील कुमार राय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (ऊपर उद्धृत)** में, रद्द कर दिया है। इसलिए, अपीलार्थी के मामले पर उपरोक्त पद के लिए अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत विचार नहीं किया गया है। अपीलार्थी का यह तर्क कि आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि तक चयन और नियुक्ति के उद्देश्य से उम्मीदवार की जो भी स्थिति होनी चाहिए, उस पर विचार किया जाना चाहिए/आवश्यक है। उपरोक्त सिद्धांत जाति की स्थिति जैसे मामलों पर लागू नहीं होता है। आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि उस/इस पद के लिए योग्यता के संदर्भ में होगी। इसमें कोई संदेह नहीं है कि श्रेणी भी समान रूप से लागू होती है, लेकिन साथ ही, एक बार जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 2016 की सरकारी राजपत्र अधिसूचना No.689 दिनांकित 23.08.2016 को 21.02.2022 पर रद्द कर दिया, तो इसका प्रभाव यह है कि अपीलार्थी की स्थिति सरकारी अधिसूचना दिनांक 19.04.2022 के माध्यम से EBC श्रेणी में बहाल हो जाएगी। अपीलार्थी को अनुसूचित जनजाति श्रेणी के संदर्भ में पद पर दावा करने का कोई अक्षम्य अधिकार नहीं है। **तेज प्रकाश पाठक और अन्य बनाम राजस्थान उच्च न्यायालय और अन्य (2013 का सीए No.2634), 2024 लाइव लॉ (एससी) 864** में रिपोर्ट किया गया, के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि केवल चयन सूची में नियुक्ति के कारण नियुक्त होने का कोई अधिकार नहीं है, लेकिन/बल्कि राज्य को बहिष्कार को उचित ठहराना चाहिए। अनुशंसा 06.05.2022 पर की गई थी और उस तारीख को, **सुनील कुमार राय और अन्य बनाम बिहार राज्य और अन्य (ऊपर उद्धृत)** के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को देखते हुए उनकी जाति अनुसूचित जनजाति श्रेणी में नहीं थी।

11. यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि साक्षात्कार की तारीख, अर्थात् 02.04.2022 को, और 06.05.2022 को अपीलार्थी के नाम की सिफारिश, सरकारी राजपत्र अधिसूचना दिनांकित 23.08.2016 जहां तक 'अनुसूचित जनजातियों की सूची में लोहार जाति' को शामिल करने की बात है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में कानून की नजर में मौजूद नहीं था। इसके अलावा चयन सूची में अपीलार्थी का नाम शामिल करने की तारीख या उसके नाम की सिफारिश की तारीख को, राज्य सरकार ने ईबीसी (EBC) के तहत आरक्षण बहाल करते हुए लोहार (एसटी) के जाति प्रमाण पत्र को रद्द करने के लिए मेमो No.6026 दिनांक 19.04.2022 के माध्यम से अधिसूचना जारी की। चयन प्राधिकारी द्वारा 06.05.2022 को इस बात की सराहना नहीं की गई थी कि अपीलार्थी का नाम अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत विचारित नहीं किया जा सकता है। अपीलार्थी की ओर से उद्धृत निर्णय मामले के तथ्यात्मक पहलुओं पर अपीलार्थी के मामले में सहायता नहीं कर रहे हैं। उन्हें अनुसूचित जनजाति के सामाजिक

आरक्षण का लाभ नहीं मिल सकता है जो कानून की नजर में 'लोहार' जाति के रूप में मौजूद नहीं है। इसके अलावा एससी/एसटी के तहत किसी भी जाति को शामिल करना संविधान के अनुच्छेद 341/342 के तहत भारत के माननीय राष्ट्रपति के पास निहित है। संविधान में अनुसूचित जनजातियों को अनुच्छेद 366(25) के तहत परिभाषित किया गया है। इसे इस प्रकार पढ़ा जाता है:

“366(25). “अनुसूचित जनजातियों” का अर्थ है ऐसी जनजातियाँ या जनजातीय समुदाय या ऐसी जनजातियों या जनजातीय समुदायों के कुछ भाग या समूह जिन्हें इस संविधान के प्रयोजनों के लिए अनुच्छेद 342 के तहत अनुसूचित जनजाति माना जाता है।

अनुच्छेद 342 में निम्नलिखित प्रकार उल्लेख है:

“342. अनुसूचित जनजातियाँ- (1) राष्ट्रपति ने किसी भी राज्य या संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में, और जहां वह एक राज्य है, उसके राज्यपाल के साथ परामर्श करने के पश्चात्, सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा, जनजातियों या जनजातीय समुदायों या जनजातियों या जनजातीय समुदायों के भीतर के भागों या समूहों को निर्दिष्ट कर सकता है जो इस संविधान के प्रयोजनों के लिए उस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के संबंध में अनुसूचित जनजाति माने जाएंगे, जैसा कि मामला हो।।

(2) संसद कानून द्वारा खंड (1) के तहत जारी अधिसूचना में निर्दिष्ट अनुसूचित जनजातियों की सूची में किसी भी जनजाति या जनजातीय समुदाय को अथवा किसी जनजाति या जनजातीय समुदाय के हिस्से या समूह को शामिल या बाहर कर सकती है, किन्तु पूर्वोक्त के सिवाय, उक्त खंड के तहत जारी की गई अधिसूचना को किसी भी पश्चातवर्ती अधिसूचना द्वारा परिवर्तित नहीं किया जाएगा।

रेखांकित आपूर्ति की गई।

राष्ट्रपति आधिकारिक तौर पर सार्वजनिक अधिसूचना के माध्यम से जातियों को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के रूप में नामित करते हैं। संसद कानून के माध्यम से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूचियों में संशोधन कर सकती है, लेकिन केवल जातियों को शामिल या

बाहर करके, न कि अपने दम पर परिवर्तन करके। दूसरे शब्दों में, राष्ट्रपति के पास प्राथमिक शक्ति होती है। साथ ही, राज्य सरकारें अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की सूची से जातियों को जोड़ या हटा नहीं सकती हैं। उपरोक्त कानूनी स्थिति के आलोक में राज्य सरकार की दिनांकित 23.08.2016 की अधिसूचना जहां तक कि अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तहत 'लोहार जाति' को शामिल करना कानून के प्राधिकार/अधिकार के बिना थी। इसलिए, यह शुरुआत से ही कानून की नजर में शून्य है।

12. अगला सवाल यह होगा कि क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का भावी प्रभाव होगा या पूर्वव्यापी प्रभाव होगा?

माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 21.02.2022 को **सुनील कुमार राय एवं अन्य बनाम बिहार राज्य एवं अन्य** (ऊपर उद्धृत) के मामले में पारित निर्णय से यह स्पष्ट नहीं है कि यह पूर्वव्यापी है या भावी। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई किसी विशिष्ट टिप्पणी के अभाव में, कोई यह अनुमान नहीं लगा सकता है कि इसका भावी प्रभाव है। पूर्वव्यापी या भावी प्रभाव से संबंधित इसी मुद्दे पर, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कनिष्क सिन्हा और अन्य बनाम पश्चिम बंगाल राज्य और अन्य के मामले में, 2025 लाइव लॉ (एससी) 259 में रिपोर्ट किया, माना कि यदि माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा इस बात पर कोई अवलोकन नहीं किया जाता है कि किसी निर्णय का भावी या पूर्वव्यापी प्रभाव है या नहीं, तो उस स्थिति में यह निष्कर्ष निकालना होगा कि इसका पूर्वव्यापी प्रभाव है।

13. इन तथ्यों और परिस्थितियों के आलोक में, अपीलकर्ता ने सी.डब्लू.जे.सी. संख्या 9632/2022 में पारित विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 13.07.2022 के आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई मामला नहीं बनाया है।

14. वर्तमान एल.पी.ए. संख्या 399/2022 खारिज की जाती है।

(पी. बी. भजंत्री, न्यायमूर्ति.)

(सुनील दत्ता मिश्रा, न्यायमूर्ति)

पी. एस/-

खंडन (डिस्क्लेमर)– स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नहीं किया जा सकता । समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।